जैसे ही पायलट के स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर होने की सूचना आई, पूरा सम्मेलन अप्रत्यक्ष रूप से पायलट के खिलाफ बयानों में बदला

पार्टी के खिलाफ काम करने वाले गलतफहमी निकाल दें, वरना हम निकाल देंगे-रंधावा

- रंधावा ने सचिन पायलट के अनशन पर कहा, अनशन से पहले मैंने जो बयान दिया, वही पार्टी का स्टैंड है, पायलट को विधानसभा में मुद्दा उठाना चाहिए था, मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ता।
- पायलट के विरोधियों का धुआँ निकालने वाले बयान पर डोटासरा ने तंज किया, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता धुआँ निकालना जानता है,वह भाजपा का धुआँ निकाल देगा।

जयपुर, 19 अप्रेल (का.प्र.)। कांग्रेस में आज दो बातें बहुत महत्वपूर्ण रही। पहली तो यह कि जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित कांग्रेस का सम्मेलन जो महंगाई राहत कैंप को लेकर बुलाया गया था, पूरी तरह से सचिन पायलट को अप्रत्यक्ष रूप से चेतावनी देने की सभा के रूप में बदल गया, तो दूसरी बात यह कि पहली बार ऐसा हुआ, जब किसी बड़े राज्य के विधानसभा चुनाव के स्टार प्रचारकों की सूची से सचिन पायलट बाहर किए गए हैं। इन दोनों बातों को देखकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस सचिन पायलट के मामले को लेकर कोई बड़ा फैसला ले चुकी है, जिसे सुनाए जाने का मजबूत आधार बनाया जा रहा है।

वैसे तो बिड़ला ऑडिटोरियम में बुधवार को कांग्रेस सम्मेलन में सचिन पायलट पायलट के नाम की प्लेट प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के बराबर लगी हुई थी, लेकिन पायलट नहीं आए। वही कार्यक्रम शुरू होने से पहले प्रभारी रंधावा अप्रत्यक्ष रूप से अनुशासनहीनता को लेकर चेतावनी देते नजर आए, उन्होंने यह भी कहा कि मैं अपने पुराने स्टैंड पर कायम हूं। कार्यक्रम के दौरान रंधावा ने कहा जो पार्टी के खिलाफ हैं, मैं उनके खिलाफ हूं। इस पर प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा खड़े हुए और कहा कि प्रभारी जो बात कह रहे हैं। वह सौ फीसदी सच है। हमें खड़े होकर उसका समर्थन करना चाहिए। इस पर मौजूद सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पहले समर्थन में हाथ खड़े किए। फिर खुद खड़े होकर इसका समर्थन किया।

वहीं पहली बार डोटासरा भी सचिन पायलट के खेतड़ी में दिए गए भाषण की अप्रत्यक्ष रुप से काट करते नजर आए। सम्मेलन में डोटासरा ने पायलट के विरोधियों का धुआं निकालने वाले बयान के अंदाज में बोलते हुए कहा कि इस सभागार में बैठा एक-एक कार्यकर्ता धुआं निकालने की ताकत रखता है। ये सब कार्यकर्ता भाजपा का धुआं निकाल देंगे। डोटासरा ने यह भी कहा कि प्रदेश प्रभारी रंधावा दिल्ली से ताकत लेकर आए हैं। सर्वे में इनकी अच्छी रिपोर्ट है। उसके आधार पर ही टिकट मिलेंगे। पार्टी सबका काम देख रही हैं। हमारे महंगाई राहत कैंपों में विधायकों से लेकर ग्राउंड के कार्यकर्ता तक को सक्रिय भागीदारी निभानी होगी।

वहीं रंधावा ने कहा कि मुख्यमंत्री ठंडे दिल के आदमी हैं। मैंने उन्हें कहा है कि सख्त बनो। मेरा साफ कहना है कि जो कांग्रेस के खिलाफ काम करेगा। मैं उसके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई की सिफारिश करूंगा। चाहे वह कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो ? मैं पंजाब से यूं ही नहीं आया हूं। राजस्थान में सरकार रिपीट करने आया हूं। आज सम्मेलन में जो माहौल है। मुझे ऐसी ही कांग्रेस चाहिए। पार्टी के खिलाफ काम करने वाले गलतफहमी निकाल दें, वरना हम निकाल देंगे। यह कहकर रंधावा ने एक बार फिर सचिन पायलट के अनशन के खिलाफ अपना रवैया स्पष्ट करने का काम किया।

वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में सरकार के काम की वजह से शानदार माहौल है। हमने सर्वे करवाया है, इस सर्वे में कांग्रेस जीत रही है। आपको बस अब हमारी योजनाओं का फायदा जनता को दिलवाना है। महंगाई राहत कैंप पर सबको फोकस करना है। गहलोत ने कहा कि हमें सरकार रिपीट करनी है। हमने इतना शानदार बजट दिया है। महंगाई राहत कैंप गेमचेंजर साबित होंगे। महंगाई राहत कैंपों से हमें हर जरूरतमंद को जोड़ना है।

कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए रंधावा ने सचिन पायलट के अनशन पर अपनी बात दोहराते हुए कहा कि अनशन से पहले मैंने जो बयान दिया, वही पार्टी का स्टैंड है। सचिन पायलट से मेरी बात होती रहती है, उनका कॉल आ गया था। याद रहे कि पायलट के अनशन से ठीक पहले 10 अप्रैल की रात को बयान जारी कर रंधावा ने पायलट के अनशन को पार्टी विरोधी गतिविधि बताया था।

वहीं अनशन के बाद कार्रवाई के सवाल पर रंधावा ने कहा कि जो बात विधानसभा में हो सकती थी। उससे बड़ा कोई प्लेटफार्म नहीं होता। वहीं पर विपक्ष बैठा था। मुख्यमंत्री बैठे थे। पूरे कांग्रेस के विधायक थे, वहीं पर भाजपा थी। बोलना चाहिए था कि हमारी सरकार ने आज तक क्या किया ? उससे बड़ा प्लेटफार्म नहीं हो सकता। सामने सीएम बैठे होते वहीं पर जवाब देते। सीएम को जवाब देना पड़ता। रंधावा ने कहा कि अनशन करना व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन जो मैंने पहले कहा है। वही पार्टी की बात है। पार्टी का वही स्टैंड है। आज भी कह रहा हूं। पायलट गवर्नर एड्रेस के समय भ्रष्टाचार की बात बोलते। गवर्नर एड्रेस ऐसी बात है, वहां पर सीएम को रिप्लाई देना पड़ता। पायलट के बैठकों में नहीं आने के सवाल पर रंधावा ने कहा कि कांग्रेस का वर्कर है। उसको इंडिविजुअल मैसेज देने का काम नहीं होता। अगर कोई बड़ा नेता है, तो उसका फर्ज बनता है कि वह यहां आए। अपने मन की बात रखे। वहीं रंधावा ने कहा मुझे राजस्थान का प्रभारी बने हुए अभी पांच ही महीने हुए हैं। राजस्थान बड़ा स्टेट है। उसको समझना है। यहां इतने बड़े नेता हैं। मैं इतनी जल्दी ऐसा कोई डिसीजन नहीं करना चाहता। जो भी डिसीजन होगा, वह पार्टी हित में होगा।

खेतड़ी की सभा में पायलट और मंत्री गुढ़ा के बयान को लेकर रंधावा बोले कि मैं हर बात को देख रहा हूं। जो कांग्रेस के लिए समस्या पैदा कर रहे हैं, उनको भी देख रहा हूं। जो कांग्रेस के लिए बिना किसी पद के लालच के काम कर रहे हैं। उनको भी मैं देख रहा हूं।

विधायक रामनारायण मीणा के कई मंत्रियों के करप्शन में डूबे होने के बयान पर वे बोले कि कितने एमएलए हैं हमारे पास। दो चार अगर क्रिटिसाइज करेंगे तो सुधार होगा। वहीं महेश जोशी पर लगे आरोपों पर कहा कि मुख्यमंत्री महेश जोशी को लेकर आपको बताएंगे। यह उनका मामला है। अगर मेरे प्रदेश कांग्रेस का कोई पदाधिकारी होता तो मैं करता। मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के बयान को लेकर भी सीएम को पूछना चाहिए। अगर वह पार्टी का उपाध्यक्ष या पदाधिकारी होता तो मैं इसका जवाब देता। हम एक-एक आदमी को सुनेंगे। दो दिन से पहले मैंने विधायकों को सुना है। मेरा फोकस 2023 का इलेक्शन है।

कर्नाटक में भाजपा युवा मोर्चा नेता की हत्या

धारवाड़, 19 अप्रेल। कर्नाटक के धारवाड़ में भाजपा युवा शाखा के एक पदाधिकारी और ग्राम पंचायत उपाध्यक्ष प्रवीण कुमार की हत्या कर दी गई है। इस घटना के बाद से माहौल गरमाया हुआ है। हुबली पुलिस ने बताया कि 18 अप्रैल की रात प्रवीण की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। तीन अज्ञात लोगों को हिरासत में ले लिया है और सभी से पूछताछ की जा रही है।

- कर्नाटक के धारवाड़ में भाजपा युवा शाखा के वरिष्ठ पदाधिकारी और ग्राम पंचायत उपाध्यक्ष प्रवीण कुमार की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है।

पुलिस अधीक्षक बी लोकेश ने कहा कि यह घटना जिले के कोट्टूर गांव में देवी उदाचम्मा देवी मंदिर उत्सव के दौरान हुई। कुछ लोग नशे की हालत में वहां पहुंचे और हंगामा किया। उन्होंने कहा कि जब कुछ लोगों ने उनसे पूछताछ की तो समूह ने उनसे झड़प शुरू कर दी। इस बीच प्रवीण के समर्थकों और विरोधी नेताओं के बीच मारपीट शुरू हो गई। कुमार बीच-बचाव करने गए तो नशे की हालत में कुछ लोगों ने चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी।

गहलोत ने पायलट...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सचिन पायलट भीड़ जुटाने वाले स्टार प्रचारक रहे हैं तथा एक के बाद दूसरे राज्य में पार्टी का प्रचार करते रहे हैं।

राजस्थान में, अशोक गहलोत उन बधुँआ समाचार चैनलों को काम में ले रहे हैं, जो मुख्यमंत्री के करीबी हैं, वे यह दिखाये कि सचिन पायलट, गहलोत द्वारा बुलाई गई "वन टू वन" मीटिंगों में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, जहाँ विधायकों को फीडबैक के लिये बुलाया जा रहा है।

सूत्रों का कहना है कि गहलोत की ओर से विधायकों को दिया जा रहा मुख्य संदेश यह है कि वे (विधायक) उनका समर्थन करते रहे। अन्यथा टिकट मिलने के मामले में उन्हें परेशानी होगी।

लेकिन इसके बावजूद, विधायक गहलोत सरकार तथा उनके मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे खुलकर उठा रहे हैं।

यह एक ऐसा विषय है जिसे मंत्री, विधायक, पार्टी नेता तथा पदाधिकारी गहलोत तथा उनकी सरकार के खिलाफ बार-बार उठाते आ रहे हैं लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस नेतृत्व झपकियाँ ले रहा है तथा गहलोत का सामना करने में असमर्थ है। और नेतृत्व इस बात को भली भाँति जानता है कि पार्टी राजस्थान में एक और सुनिश्चित पराजय की और बढ़ रही है।

'समलैंगिक विवाह केस में राज्यों...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एक अन्य ताजा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से यह अनुरोध किया है कि इस मामले में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को भी पक्षकार बनाया जाए।

सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि केन्द्र सरकार गत 18 अप्रेल को सभी राज्यों को पत्र लिख चुकी है, जिसमें याचिकाओं की वर्तमान खेप में उठाए गए लैंगिक मुद्दे पर उनकी टिप्पणियां मांगी गई हैं। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा वर्तमान प्रकरण के मूल तक जाता है तथा इसके मायने दूरगामी हैं।

उन्होंने शीर्ष अदालत से अनुरोध किया कि या तो सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को केस में शामिल किया जाए, अन्यथा एक विकल्प के तौर पर केन्द्र सरकार को सभी राज्यों के साथ परामर्शी प्रक्रिया पूर्ण कर उसका संकलन कोर्ट के सम्मुख प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए तथा वर्तमान मुद्दे पर उसके बाद ही निर्णय किया जाए।

प्रस्तुत किए गए ताजा शपथ पत्र में केन्द्र सरकार का मंतव्य बिल्कुल स्पष्ट है कि राज्यों के अधिकार, खासतौर पर इस विषय पर कानून बनाने के अधिकार पर इस संबंध में दिए जाने वाले किसी भी निर्णय से प्रभाव पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत इस शपथ पत्र में केन्द्र सरकार ने कहा है कि विभिन्न राज्यों ने अपनी विधिक शक्तियों के अनुरूप इस विषय पर पहले ही कानून बना लिए हैं, अतः वर्तमान केस में उन्हें एक अनिवार्य एवं उचित पार्टी के रूप में सुना जाना जरूरी है।

केन्द्र सरकार ने अपने शपथ पत्र में निवेदन किया है इस मामले में जहां संविधान की सातवीं सूची के अन्तर्गत राज्यों के विधायी अधिकार एवं उन राज्यों के निवासियों के अधिकार स्पष्ट रूप से सवालों के घेरे में है, इसलिए याचिकाकर्ताओं का यह परम कर्त्तव्य है कि वे वर्तमान मुकदमे में सभी राज्यों को एक पक्षकार बनाएं।

अब तो मुख्यमंत्री का भाषण भी लीक होने लगा!

मुख्यमंत्री गहलोत को भाषण 4 बजे देना था, लेकिन वे क्या बोलेंगे, ढाई घंटे पहले सोशल मीडिया पर भेज दिया गया

- 17 अप्रैल के वन-टू-वन संवाद कार्यक्रम में भी ऐसा ही हुआ था, जब कार्यक्रम 11 बजे शुरू होना था, पर दस बजे ही मीडिया को बता दिया गया कि, कार्यक्रम में सचिन पायलट पर कोई बात नहीं हुई। कार्यक्रम शुरू होने से पहले यह कैसे पता चल सकता है कि, कार्यक्रम में क्या नहीं हुआ।
- इससे इन अटकलों को बढ़ावा मिल रहा है कि, कोई निजी एजेंसी मुख्यमंत्री के भाषण के पॉइन्ट्स तय कर रही है और निर्धारित समय से पहले ही सोशल मीडिया पर पॉइन्ट्स जारी कर रही है।
- राजनैतिक हल्कों में चर्चा है कि, मुख्यमंत्री गहलोत, जो 50 साल से राजनीति में हैं, क्या उन्हें भी निजी एजेंसी से पूछ कर भाषण के पॉइन्ट्स तय करने पड़ रहे हैं।

जयपुर, 19 अप्रेल (का.प्र.)। राजस्थान में पेपर लीक की घटनाएं लगातार होती रही हैं, लेकिन यदि राजस्थान के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भाषण ही लीक हो जाए,तो फिर इसे क्या कहा जाएगा।

यह घटना बुधवार को बिड़ला ऑडिटोरियम में घटित हुई,जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना भाषण तो करीब 4 बजे के आसपास दिया, लेकिन मुख्यमंत्री क्या बोलेंगे, यह तमाम पॉइन्ट्स विभिन्न समाचार पत्रों के संपादक और कुछ चुनिंदा रिपोर्टरों के पास मुख्यमंत्री के भाषण के ढाई घंटे पहले ही पहुंच गए और ये पॉइन्ट्स सोशल मीडिया के जरिए सब जगह पहुंच गए। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री अपना भाषण देने से पहले जो पॉइन्ट्स तय करते है वे खुद करते हैं या कोई और तय करता है, और मुख्यमंत्री उसके अनुरूप अपना भाषण देते हैं।

दरअसल यह घटना पहली बार नहीं हुई है। पिछले 3 दिन के दौरान दूसरी बार ऐसा हुआ है, जब मीडिया को कांग्रेस कार्यक्रम के कवरेज के दौरान किसी निजी एजेंसी ने अपने अनुरूप चलाने का प्रयास किया है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री का भाषण शुरू होने के ढाई घंटे पहले ही उनके भाषण में शामिल होने वाले पॉइन्ट्स सोशल मीडिया के जरिए विभिन्न समाचार पत्रों के संपादकों और पत्रकारों तक पहुंचाने का काम किया गया है।

ऐसा पहली बार 17 अप्रैल को हुआ जब कांग्रेस ने राजस्थान में सरकार रिपीट कराने के प्रयासों के तहत विधायकों के साथ वन टू वन संवाद कार्यक्रम शुरू किया। यह कार्यक्रम 17 अप्रैल 2023 को सुबह 11:00 बजे के बाद शुरू होना था, लेकिन संपादकों और कुछ चुनिंदा रिपोर्टर्स के सोशल मीडिया पर करीब 10:00 बजे ही कुछ स्पेशल पॉइंट सोशल मीडिया के जरिए पहुंचा दिए गए। जिनमें महत्वपूर्ण पॉइन्ट्स यह था कि संवाद कार्यक्रम में सचिन पायलट को लेकर कोई भी चर्चा नहीं हुई। यहां सवाल यह उठता है कि आखिरकार जो कार्यक्रम ही 11:00 बजे शुरू होना था, उसमें क्या नहीं हुआ, यह 10:00 बजे ही सोशल मीडिया पर भेज दिया गया। जबकि हकीकत यह थी कि संवाद कार्यक्रम के पहले ही दिन 17 अप्रैल को सचिन पायलट ही प्रमुख मुद्दा बने रहे।

वैसे ही 19 अप्रैल को कांग्रेस ने बिड़ला ऑडिटोरियम में 1 दिन का सम्मेलन रखा, जिसमें मुख्यमंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में करीब 4:00 बजे अपना भाषण देना था, लेकिन 1:30 से 1:45 बजे ही मुख्यमंत्री क्या भाषण देंगे, इस संबंध के कुछ पॉइंट विभिन्न समाचार पत्र और न्यूज़ चैनल के संपादकों और पत्रकारों के सोशल मीडिया एकाउंट पर पहुंच गए और सवाल यह उठता है कि क्या अब मुख्यमंत्री,जो कि 50 साल से ज्यादा राजनीति कर चुके हैं, उनको भी अब किसी निजी एजेंसी या निजी व्यक्ति से पूछ कर या पॉइंट तय करा कर भाषण देना पड़ रहा है। इस बात की चर्चा मीडिया जगत में बड़ी जोर शोर से हो रही है।

जहां तक किसी निजी एजेंसी की ओर से सरकार का प्रचार करने का सवाल है,तो सभी सरकारें इस तरह का काम करती आई है,या नेता निजी स्तर पर भी एजेंसियों की सेवा लेते रहे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि सरकार 3 घंटे बाद क्या करेगी या मुख्यमंत्री 3 घंटे बाद क्या भाषण देंगे, यह शब्द भी निजी एजेंसी तय कर रही है।

पहली बार कांग्रेस "मीडिया वॉर" ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कर्नाटक के उन किसानों के खिलाफ है जिन्होंने दूध के व्यवसाय से काफी धन कमाया है।

यह तो तयशुदा बात है कि नन्दिनी बनाम अमूल मुद्दे ने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के मन में जगह बना ली है तथा वहाँ के किसानों के मन यह मुद्दा गूँज रहा है। कुछ भी लिये बिना ही, कांग्रेस के हाथों में भाजपा को मात देने का मुद्दा आ गया है कांग्रेस, जो प्रायः बल्कि सदैव ही, मीडिया-प्रबंधन एवं धारणा-निर्माण के मामले में फिसड्डी रहती है, इस मुद्दे को लेकर भाजपा पर बहुत भारी पड़ती दिखाई दे रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनावों के मामले में तो कम से कम ऐसा ही रहा है।

पूर्व मुख्यमंत्री एस. सिद्धारमैया ने सोच समझकर एक ट्वीट कर, सूडान जहाँ जबर्दस्त गृह युद्ध शुरु हो गया है, में फंसे भारतीयों को मदद देने अपील की है। इस पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने जो प्रतिक्रिया दी है, उससे कांग्रेस को उन्हें एक खलनायक के रूप में प्रस्तुत करने की नयी सामग्री मिल गई है।

सिद्धारमैया, जिन्होंने विदेशी मंत्री से सहायता माँगी थी, के ट्वीट पर उन्होंने जवाब दिया कि कांग्रेस नेता युद्ध जैसी स्थिति में फँसे लोगों को लेकर राजनीति कर रहे हैं। जयशंकर ने ट्वीट में कहा था, "आपके ट्वीट से विस्मित हूँ। वहाँ लोगों की जिन्दगी दाँव पर लगी है, राजनीति मत कीजिये। 14 अप्रैल से, जब से वहाँ लड़ाई शुरु हुई है, खार्तूम का भारतीय दूतावास सूडान के अधिकांश भारतीय नागरिकों तथा पी.आई.ओ.'ज़ के सम्पर्क में है।"

- सिद्धारमैया ने विदेश मंत्री को ट्वीट करके जानकारी चाही कि, उन कन्नड़वासियों की क्या स्थिति है, जो सूडान के गृह युद्ध में फंसे हुए हैं, विदेश मंत्री जयशंकर ने जवाब दिया, "कृपया सूडना में फंसे कन्नड़वासियों को तो राजनीति का मुद्दा न बनायें।"
- पूर्व मु.मंत्री सिद्धारमैया व आई.सी.सी. के मीडिया प्रभारी जयराम ने जयशंकर के कथन पर कटाक्ष करना शुरू कर दियाः "क्या अपने देशवासियों के हालचाल की जानकारी लेना राजनीति करना है। "इस मुद्दे पर कर्नाटक की जनता में कांग्रेस के स्टैण्ड के प्रति सहानुभूति है।"

विदेश मंत्री के इस बयान पर कांग्रेस नेताओं तथा आम लोगों ने ट्विटर पर तीखी प्रतिक्रियाएँ दी हैं।

वस्तुतः इस पर सिद्धारमैया की प्रतिक्रिया बहुत ही कारगर और प्रभावी रही। उन्होंने विदेश मंत्री को टैग करते हुये, जवाबी ट्वीट किया, "डॉ. जयशंकर, चूँकि आप विदेश मंत्री हैं, इसलिये मैंने आपसे मदद की अपील की है। अगर आप विस्मय में व्यस्त है, तो हमें उस व्यक्ति का पता दे दीजिये, जो हमारे लोगों की वापसी में मदद कर सके। ऐसी जानकारी मिली है कि कर्नाटक की हक्की-पक्की जनजाति के 31 लोग सूडान में असहाय स्थिति में हैं, जो गृह युद्ध के दौर से गुजर रहा है इसलिए मैं पी.एम.ओ. इंडिया, नरेन्द्र मोदी, एच.एम.ओ. इंडिया, एम.ई.ए. इंडिया तथा बी.एस. बोम्मई से हस्तक्षेप करने तथा उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूँ।"

कांग्रेस इस संदेश को आम जनता तक पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं से कह दिया है कि विदेश मंत्री के इस जवाब को राज्य के कोने-कोने तक पहुँचा दें।

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता तथा मीडिया प्रभारी ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री को दिये गये एम.ई.ए. जयशंकर के "अत्यधिक विस्मयकारी जवाब" को लेकर उन पर जबरदस्त प्रहार किया है। ज्ञातव्य है कि कर्नाटक के पूर्व मुख्य केन्द्रीय विदेश मंत्री से राज्य के उन आदिवासियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने का अनुरोध कर रहे थे, जो गृह युद्ध में घिर चुके सूडान में फँसे हुये हैं।

सिद्धारमैया पर प्रहार करने वाले जयशंकर के जवाब पर टिप्पणी करते हुये जयराम रमेश ने कहा, "एक ऐसे व्यक्ति द्वारा इतने अप्रिय स्तर की प्रतिक्रिया, जिसे मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ ..... जिसने अब नई निष्ठाएं विकसित कर ली हैं तथा वह जो कुछ भी कहता एवं करता है, उसमें वह इस चीज को प्रदर्शित करना भी चाहता है।"

एस.ओ.जी. के ए.डी.जी. अशोक राठौड़ ने प्रेस वार्ता कर सैकेंड ग्रेड भर्ती पेपर लीक मामले में कई बड़े खुलासे किए

उन्होंने बताया कि आर.पी.एस.सी. सदस्य बाबूलाल कटारा ने 60 लाख रुपए में शेर सिंह को पेपर बेचा था

- राठौड़ के अनुसार पेपर सैट करने का जिम्मा बाबूलाल कटारा के पास था और उसने परीक्षा से दो हफ्ते पहले ही शेर सिंह को पेपर दे दिया था।
- राठौड़ ने बताया, "शेरसिंह ने 80 लाख रुपए में भूपेन्द्र सारण को यह पेपर दिया था, जिसे उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पांच से आठ लाख रुपए में कई अभ्यर्थियों को बेचा था।"
- उन्होंने आगे कहा, "पुलिस जांच में सामने आया कि बाबूलाल कटारा के भांजे विजय ने शेर सिंह से पेपर लीक की प्लानिंग के एवज में सोने का कड़ा लिया था।"

जयपुर, 19 अप्रेल (कासं)। सैकेंड ग्रेड टीचर भर्ती का पेपर राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) के गिरफ्तार सदस्य बाबूलाल कटारा ने ही 60 लाख रुपए में शेरसिंह को बेचा था। इस मामले का खुलासा करते हुए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) के एडीजी ने बुधवार को जयपुर में एसओजी मुख्यालय में प्रेसवार्ता कर बताया कि कटारा ने वाइस प्रिंसिपल शेरसिंह मीणा को 60 लाख रुपए में पेपर बेचा था। शेरसिंह ने 80 लाख रुपए में भूपेंद्र सारण को यह पेपर दिया। आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा, उसके भांजे विजय कटारा और चालक गोपाल को बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से तीनों को 29 अप्रैल तक रिमांड पर भेजा दिया गया है।

राठौड़ ने बताया कि शुरुआती जांच में एसओजी को पता चल गया था कि पेपर किसी परीक्षा केंद्र से लीक नहीं हुआ है। इस दौरान पुलिस टीम ने हर जगह सर्च किया। इसके बाद इनपुट मिलने के आधार पर विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने आरपीएससी चेयरमैन से संपर्क किया गया। उन्हें कहा कि पेपर की चैन ऑफ कस्टडी देखी जाए। इससे पता चल सकेगा की किस-किस व्यक्ति के पास पेपर की एक्सेस थी।

राठौड़ ने बताया कि दिसंबर से लेकर अप्रैल तक पुलिस टीम ने एक-एक कर इस गिरोह के सदस्यों को पकड़ना शुरू कर दिया। इस गिरोह के सदस्यों से हुई पूछताछ के बाद एसओजी को पता चला की आरपीएससी के एक सदस्य ने पेपर लीक किया है। जिस पर मंगलवार सुबह टीम को अजमेर भेजा गया। इसके बाद तीनों आरोपियों की गिरफ्तार हुई। एसओजी अफसरों का दावा है कि मामले में फरार चल रहे सुरेश ढाका को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि पेपर सैट करने का जिम्मा बाबूलाल कटारा के पास था। उसने पेपर शुरू होने से 2 हफ्ते पहले ही शेर सिंह को हाथ से लिखा पेपर दे दिया था। शेर सिंह ने कटारा को दो किस्तों में 60 लाख रुपए का भुगतान किया था। शेर सिंह ने इस पेपर को जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में टाइप करा कर भूपेंद्र सारण को बेचा था। भूपेंद्र फिर इस पेपर को आगे देता चला गया। इस बीच भूपेन्द्र सारण ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस पेपर को पांच से आठ लाख रुपए में कई अभ्यर्थियों को बेच दिया। इस मामले में विजय और गोपाल सिंह को कितना पैसा बाबूलाल ने दिया इसकी भी जांच की जा रही है।

अशोक राठौड़ ने बताया कि पेपर सैट करने की जिम्मेदारी आरपीएससी ने सदस्यों को दी थी। पेपर को प्रिंटिग प्रेस में भेजने की कॉपी सदस्यों के पास थी। कटारा का अपने ड्राइवर के जरिए शेर सिंह से संपर्क हुआ था। इसके बाद शेर सिंह पेपर लेकर जयपुर आया। जांच के दौरान पुलिस को पता लगाने में बड़ी परेशानी हुई की पेपर किसने सैट किया। आरपीएससी का कहना था कि पेपर सेट करने वालों का नाम गोपनीय रखते हैं। जब जांच की गई तो पता चला कि शेर सिंह को पता था कि पेपर बाबूलाल सेट कर रहा है। इसलिए ड्राइवर के जरिए कटारा से संपर्क किया। इससे आरपीएससी की गोपनीयता पर ही सवाल उठ रहे हैं। हैरानी की बात है कि एक ही सदस्य छह के छह पेपर सैट कर रहा था।

एडीजी ने बताया कि जांच में सामने आया कि मामले में बाबूलाल कटारा का भांजा विजय कटारा भी लिप्त है। उसने शेर सिंह से पेपर लीक की प्लानिंग करने के एवज में सोने का कड़ा लिया था। शेरसिंह और विजय के संबंध अच्छे थे। इस पर विजय ने शेरसिंह से पैसा न लेकर सोने का कड़ा लिया। एसओजी ने आभूषणों की वह दुकान भी ढूंढ निकाली है, जिससे सोने का कड़ा खरीदा गया था। बाबूलाल कटारा की शेर सिंह मीणा से चार साल पहले दोस्ती हुई थी। शेर सिंह मीणा ने बाबूलाल को आरपीएससी से भर्ती परीक्षाओं के पेपर आउट कर मुनाफा कमाने के लिए मना लिया था। कटारा के मन में पेपर लीक से मिलने वाले पैसों का लालच तो था, लेकिन डर भी था। कटारा पेपर माफिया के ज्यादा संपर्क में नहीं रह सकता था। आरपीएससी के अधिकारियों और दूसरे कर्मचारियों को उस पर शक हो सकता था। ऐसे में कटारा को किसी विश्वासपात्र की जरूरत थी। डूंगरपुर में रहने वाला उसका भांजा विजय बेरोजगार था। उसे काम की जरूरत थी। इस पर बाबूलाल ने उसे अपने साथ मिला लिया। बाबूलाल अपने घर या बाहर के सभी जरूरी काम विजय से ही करवाता था।

अशोक राठौड़ ने बताया कि बाबूलाल कटारा को पहले से ही अपनी गिरफ्तारी का अंदेशा था। जब एसओजी के डीआईजी सतवीर सिंह उसके अजमेर स्थित घर पहुंचे तो उसने किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं किया। प्रारंभिक पूछताछ में उसने कई खुलासे किए हैं। अभी भी पेपर लीक मामले में 10 से अधिक लोग एसओजी की गिरफ्त में नहीं आए हैं। इनकी तलाश की जा रही है। अब बाबूलाल कटारा समेत तीनों को एक साथ वाइस प्रिंसिपल शेर सिंह मीणा के सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। शेर सिंह को पहले ही दस दिन की रिमांड पर लिया जा चुका है।

उधर अब एसओजी ने फरार चल रहे पेपर लीक के मास्टरमाइंड सुरेश ढाका की तलाश में डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ में छापेमारी शुरू कर दी गई है। एसओजी को उसके बारे में कुछ जानकारी मिली है। उसके बाद बुधवार सुबह से सर्च शुरू कर दिया गया है। इस पूरे मामले में अब तक करीब पचास से ज्यादा लोगों को पकड़ा जा चुका है।

'ममता बनर्जी ने अमित शाह को...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ममता बनर्जी के लिए तृणमूल कांग्रेस का एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा एक चटपटा विषय रहा है। वह भाजपा के विरूद्ध विपक्ष के संयुक्त गठबंधन की नेता एवं चेहरा बनना चाहती हैं, लेकिन एक क्षेत्रीय पार्टी की नेता के रूप में वह स्वयं की एक राष्ट्रीय भूमिका का शायद ही दावा कर सकती थीं।

राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेन्दु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि बनर्जी ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को फोन किया और उनसे मांग की कि वह तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बहाल करने के लिए हस्तक्षेप करें। यह बात सार्वजनिक होने पर, ममता बनर्जी क्रोध में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, यदि आरोप सत्य साबित होता है तो वो सीधे ही इस्तीफा दे देंगी। ममता बनर्जी के तिलमिलाने का एक कारण यह है कि, यह तीर सुवेन्दु अधिकारी की तरफ से आया है। जो कि इन्हीं सुवेन्दु अधिकारी ने ममता बनर्जी का उनकी पुरानी सीट नन्दीग्राम में शिकस्त दी थी।

पिछले विधानसभा चुनावों में अधिकारी ने ममता बनर्जी से नन्दीग्राम सीट छीन ली थी। अधिकारी पर तीखे प्रहारों और मतों की अनेकों बार हुई गणना के बावजूद, अंतिम गणना में सुवेन्दु अधिकारी ही विजयी घोषित हुए।

इसके बाद, ममता बनर्जी को दूसरी सीट, भवानीपुर से चुनाव लड़ना पड़ा, जबकि, उनकी पार्टी का एक प्रत्याशी पहले ही इस सीट को जीत चुका था।

इसलिए, गृह मंत्री अमित शाह को ममता बनर्जी द्वारा फोन करने के अधिकारी के आरोप ने ममता को व्यक्तिगत आघात पहुँचाया। वे पश्चिम बंगाल के अलावा अन्य राज्यों में कुल सीटें हासिल करने के लिए बहुत मेहनत कर रही थीं। नैशनल पार्टी का स्टेटस पाने के लिए किसी भी पार्टी को "स्टेट पार्टी" होना जरूरी है तथा राज्य विधानसभाओं में उसकी निर्धारित संख्या में सीटें होनी चाहिए।

बनर्जी की पार्टी, गोवा, मिज़ोरम, त्रिपुरा एवं उत्तर पूर्वके कई राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है। तथापि, किसी भी राज्य में उनका खाता नहीं खुला।

गोवा में कुछ प्रमुख कांग्रेसी नेता गत चुनावों से पूर्व उनकी पार्टी में शामिल हुए थे, पर उनका कोई भी प्रत्याशी जीत नहीं सका कुछ की तो जमानत भी जब्त हो गई।

राज्य के चुनावों के बाद जो उनकी पार्टी में आए थे वे भी छोड़ गए और बोले की तृणमूल साम्प्रदायिक मुद्दे पर काम करती है। त्रिपुरा में ममता बनर्जी को स्थानीय बंगाली समुदाय का समर्थन मिलने की उम्मीद थी पर यहां भी उनकी रणनीति फेल हो गई।

'इस साल भारत चीन से...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हो जाएंगे। वैश्विक आबादी को लेकर यूनाइटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फण्ड की एक रिपोर्ट कहती है कि इस वर्ष के मध्य तक अमेरिका की आबादी 340 मिलियन हो जाएगी और आबादी के हिसाब से विश्व में उसका नम्बर तीसरा होगा।भारत और चीन में विश्व